SHRI CHITTA BASU: That was one part.

MR. CHAIRMAN: That was the operative part.

SHRI CHITTA BASU: That was one part. Another part was, various committees including the Planning Commission...

MR. CHAIRMAN: He knows it. Everybody knows it. Every Member knows it. It is a statement of fact. (*Interruptions*) Put your question. He can answer only questions.

SHRI CHITTA BASU: I would like to know whether it is a fact...

MR. CHAIRMAN: There have been several committees. You know it. He knows it.

SHRI CHITTA BASU: He should say.

MR. CHAIRMAN: Mr. Minister, do you know that there have been many committees...

AN HON. MEMBER: He wants another committee to be appointed.

SHRI CHITTA BASU: He referred to the monitoring aspect of the twenty-point programme.

MR. CHAIRMAN: You restrict yourself to your supplementary. You do not open up everything.

SHRI CHITTA BASU: He has not answered the first part of my question.

MR. CHAIRMAN: Question No. 164.

Loans for housing development in Madhya Pradesh

*164. SHRI SURESH PACHOURI: Will the Minister of URBAN DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Housing Development Finance Corporation has not disposed of the loans for Madhya Pradesh for housing development, so far;

(b) if so, what are the reasons therefor; and

(c) the amount given to Madhya Pradesh during 1989-90 for housing development?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT (SHRI DALBIR SINGH): (a) No, Sir. Housing Development Finance Corporation does not allocate funds State-wise but sanctions as many eligible loan applications as applied for and which conform to their norms. The loans sanctioned by the Indore Branch since inception amount to Rs. 7.27 crores.

(b) Does not arise, in view of (a) above.

(c) The Indore Branch of HDFC during the first quarter of 1989-90 has sanctioned loans amounting to Rs. 3.72 crores for construction of 550 housing units.

श्री सुरेश पचौरी : माननीय सभापति जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या हाउसिंग डेवलपमेंट कारपोरेशन ग्रामीण क्षेत्रों में भी ऋण की व्यवस्था करता है ? साथ ही एच० डी०एफ०सी० द्वारा दिए जाने वाले ऋणों की क्या शर्तें हैं ?

श्री दलबीर सिंह : सर, एच०डी०एफ० सी० ग्रामीण क्षेत्रों में भी लोन देता है। दूसरा जो सवाल है कि इसकी शर्तें क्या हैं, तो पहले तो एच०डी०एफ०सी० यह देखती है कि जो कोई भी इन्डीविजुअल लोन चाहता है तो उसके पास क्या अचल सम्पत्ति है और यदि कोई नौकरी करता है, वाईफ या हसबैंड, तो उनकी क्या री पे करने की केपेसिटी है ? तो इस तरह से उसकी जो नार्म्स हैं, वह बराबर दोनों को देखती है और सभी नार्म्स तय कर लेती है और उनको कर्ज देती है। जहां तक ग्रामीण क्षेत्रों के लिए बूत है, तो ग्रामीण क्षेत्रों को कोई बंधन नहीं है, एच०डी०एफ०सी० के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों को भी ऋण दिया जाता है।

श्री सुरेश पचौरी : मान्यवर, मंत्री जी ने जो नार्म्स बताई के उसअनुसार तो

यह लगता है कि केवल बड़े लोगों को ही ऋण मिल सकता है, गरीबों को नहीं मिल सकता ।... (व्यवधान)...

श्री सभापति : यह सवाल तो न हुआ आपका ।... (व्यवधान)...

श्री सुरेश पचौरी : अपने उत्तर में इन्होंने हाउसिंग यूनिट पर ऋण देने की बात कही है । मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहूंगा कि क्या एच०डी०एफ०सी० द्वारा राज्यों की हाउसिंग एजेंसियों को भी ऋण प्रदान करने की व्यवस्था है ? यदि है, तो अब तक कितना ऋण कौन प्रदेश की हाउसिंग एजेंसियों को प्रदान किया गया ?

श्री दलबीर सिंह : ओफिशियल, मार्च, 1989 तक 7.27 करोड़ दिया है और अभी जो हमारा क्वार्टर 1989-90 का है उसमें 3.72 करोड़ दिया है । एडीशनल बोर्ड की है इसमें 31 मार्च, 1989 में एच. डी० एफ०सी० ने जो मंजूरी दी है वह 2.31 करोड़ है 25-7-89 तक जो ऋण एच.डी.एफ.सी. ने मंजूर किया है ।

SHRIMATI VEENA VERMA: Sir, I would like to know, what is the total number of applications received by banks in Madhya Pradesh, particularly from weaker sections, and to how many you have not granted the loan? I would also like to know whether there is any machinery to ensure that the money is actually used for house construction.

श्री दलबीर सिंह : ओफिशियल, इसमें खास तौर से 1000 बीपीएल को लोन मंजूर किया गया है । जहां तक माननीय सदस्या का कहना है कि लोअर लेवल के लोगों को लिया मंजूर किया है, एच०डी०एफ० सी० कोशिश कर रहा है कि मध्य प्रदेश में खासकर ग्रामीण अंचलों में भी इनको देखेंगे ।

जहां तक लोअर इनकम ग्रुप का सवाल है उनको कवर करने की उनकी योजना है ।

Committee for Regularisation of Colonies in Delhi

165. SHRI BIR BHADRA PRATAP SINGH: Will the Minister of URBAN DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government had appointed a Committee to look into the aspect of regularisation of colonies in Delhi;

(b) whether the said Committee has since submitted its report to Government; and

(c) if so, what are the names of the colonies recommended for regularisation and by when these are likely to be regularised?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT (SHRI DALBIR SINGH): (a) to (c) Lt. Governor of Delhi had appointed a Committee. The recommendations of this Committee are still under consideration of Delhi Administration.

SHRI BIR BHADRA PRATAP SINGH: Sir, some years ago I had made special mention about this and still there is a Committee which is considering the matter. I do not know for how many more years it will go on considering this. My first supplementary is: will the Government consider providing civic amenities, such as water, sanitation and electricity along with regularisation of these colonies?

श्री दलबीर सिंह: श्रीमान यह अहम् सवाल है और न केवल दिल्ली का है बल्कि और शहरों का भी है जहां तक दिल्ली का सवाल है, अभी कंसिडरेशन में है और बराबर हमारा इस ओर ध्यान है जितनी जल्दी यह रिपोर्ट आ जाएगी, इनको हम लागू करेंगे, लेकिन सिविक ऐमिनिटीज हम उनको सभी प्रकार की दे रहे हैं ।

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES (SHRI JAGDISH TYTLER): Sir, with your